



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 चैत्र 1946 (श०)  
(सं० पटना 385) पटना, सोमवार, 15 अप्रील 2024

सं० 08/नि०था०-11-30/2014 सा०प्र०-2674  
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

13 फरवरी 2024

श्री जियाउद्दीन अहमद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-325/2011 तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, मुजफ्फरपुर पूर्वी सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों के साथ मिलकर साजिश रचते हुए श्रीमती जुलेखा खातून, पत्नी स्व० कुर्बान मंसूरी की भूमि का दाखिल खारिज गलत मोखतारनामा एवं गलत केवाला के आधार पर किये जाने तथा फर्जी महिला सीताबाई उर्फ फातिमा मंसूरी का नाम दर्ज कराते हुए खाता संख्या-1021 में से 06 (छः) डिसमिल जमीन अपने साला के नाम से लिखवाने संबंधी प्रतिवेदित आरोपों तथा इन्हीं आरोपों पर श्री अहमद को निगरानी विभाग द्वारा (निगरानी थाना कांड संख्या-23/06 दिनांक 21.04.2006) हिरासत में लिए जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3320 दिनांक 28.03.2007 द्वारा श्री अहमद को निलंबित किया गया एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7215 दिनांक 13.07.2007 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2986 दिनांक 24.02.2012 द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से सेवा से बर्खास्त किया गया।

उक्त दंड के विरुद्ध श्री अहमद द्वारा मा० उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-5843/2012 दायर किया गया, जिसमें मा० उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 05.11.2012 को पारित आदेश में विभागीय संकल्प-2986 दिनांक 24.02.2012 को निरस्त करते हुए आदेश दिया कि विभाग (प्रतिवादी) चाहे तो पुनः नये सिरे से विभागीय कार्यवाही आरंभ कर सकते हैं।

मा० उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में संकल्प ज्ञापांक 3501 दिनांक 27.02.2013 द्वारा दंडादेश संकल्प ज्ञापांक 2986 दिनांक 24.02.2012 को निरस्त कर दिया गया तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 17576 दिनांक 14.11.2013 द्वारा पुनः विहित रिति के अनुरूप श्री अहमद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। श्री अहमद दिनांक 31.07.2014 को सेवानिवृत्त हो गये, अतएव उनके विरुद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाई को आदेश संख्या-17936 दिनांक 29.12.2014 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी०) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

संचालन पदाधिकारी यथा अपर विभागीय जांच आयुक्त सह प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 210 दिनांक 06.10.2016 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 05.11.2012 को पारित न्यायादेश के अनुरूप जांच नहीं किये जाने के कारण (गवाहों का परीक्षण/प्रतिपरीक्षण) अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले की अग्रेत्तर जांच कराने का

निर्णय लिया गया। तदालोक में पत्रांक-12494 दिनांक 11.09.2019 द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना को मूल रूप में वापस करते हुए अग्रेतर जांच करने का आदेश दिया गया।

प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग-सह-जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 129 दिनांक-21.9.2023 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें आरोप संख्या-01 एवं 02 को प्रमाणित एवं आरोप संख्या-03 को अप्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रति श्री अहमद को उपलब्ध कराते हुए विभागीय पत्रांक-18760 दिनांक 06.10.2023 द्वारा लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

श्री अहमद द्वारा अपना लिखित अभिकथन पत्रांक-शून्य दिनांक 10.11.2023 समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा मुख्य रूप से कहा गया है कि अंचलाधिकारी द्वारा जमाबंदी रैयत स्व0 कुर्बान मंसूरी की पहली पत्नी के नाम से जमाबंदी पंजी में की गयी प्रविष्टि का सुधार करते हुए उनके द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता के रूप में प्राप्त शक्तियों के तहत उनकी दुसरी पत्नी सीता बाई उर्फ फातिमा मंसूरी का नाम सम्यक सूनवाई एवं साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए संशोधन/जमाबंदी सुधार का आदेश पारित किया गया था। उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र के उपर जाकर कार्य करने के आरोपों को नकारा है। साथ ही अपने कथन एवं तर्क को कई न्यायादेशों से पुष्टि होने एवं माननीय न्यायालय-सब-जज-III, मुजफ्फरपुर द्वारा स्वत्व वाद संख्या-351/04 में की गयी टिप्पणी का हवाला देते हुए अपने विरुद्ध प्रमाणित आरोपों को नकारा है।

विविध वाद संख्या 92/03-04 में अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उसे जमाबंदी सुधार वाद मानने एवं कार्रवाई करने तथा प्रश्नगत खेसरा के अंश 06 डिसमिल जमीन अपने साले के नाम से लिखवाने के आरोपों को नकारते हुए उन्होंने कहा है कि अपने साले से उनका कोई लेना-देना नहीं है। निगरानी पुलिस निरीक्षक ने भी अपने परीक्षण प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वीकार किया है कि उनके साले के द्वारा कथित रूप से जमीन क्रय करने के संबंध में उनके आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय आदि का उन्होंने जांच नहीं किया।

श्री अहमद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप तथा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री अहमद ने अपने लिखित अभिकथन में उन्हीं बातों को दोहराया है, जो संचालन पदाधिकारी के समक्ष बचाव ब्यान में दिया गया था, कोई नये तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है जिस पर विचार किया जा सके। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में समीक्षा करते हुए जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है तथा आरोप संख्या-01 एवं आरोप संख्या-02 को “प्रमाणित” एवं आरोप संख्या-03 को “अप्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित पाया” गया।

अतः संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के प्रावधानों के तहत श्री अहमद के “पेंशन से 50 (पचास) प्रतिशत की कटौती 05 (पाँच) वर्षों तक करने” का दंड अधिरोपित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-22777 दिनांक 15.12.2023 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-4371 दिनांक 31.01.2024 द्वारा विभागीय प्रस्ताव को बिना परामर्श के वापस करते हुए यह उल्लेख किया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-9794 दिनांक 22.07.2019 की कड़िका-07 में प्रावधान है कि:-“वैसे अनुशासन संबंधी पेंशन से कटौति अथवा वृहद् दंड के मामले में, जिनमें आयोग द्वारा परामर्श/सहमति दी गयी हो और बाद में पेंशन से कटौति अथवा वृहद् दंड के आदेश को निरस्त करने, कम करने अथवा रूपभेदित किये जाने की स्थिति में पुनः आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।”

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री जियाउद्दीन अहमद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-325/2011 तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, मुजफ्फरपुर पूर्वी, सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43 (बी0) के संगत प्रावधानों के तहत उनके “पेंशन से 50 (पचास) प्रतिशत की कटौती 05 (पाँच) वर्षों तक करने” का दंड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अंजुला प्रसाद,  
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 385-571+10-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>